ग्लोंबल एक्शन वीक फॉर एजूकेशन (GAME)

ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजूकेशन (जीसीई) अपने सदस्य देशों के नेशनल कोएलीशन्स के साथ मिलकर शिक्षा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और सरकारों का ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से हर वर्ष ग्लोबल एक्शन वीक फॉर एजूकेशन के नाम से एक विश्वव्यापी अभियान संचालित करता है। भारत में नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के साथ इस अभियान को संचालित किया जाता है। इस वर्ष यह अभियान 24 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019 के बीच शिक्षक संगठनों एवं नागर संमाज संस्थाओं के साथ मिलकर देश के 25 राज्यों में आयोजित किया गया। हर वर्ष एक सप्ताह तक मनाया जाने वाला अभियान इस बार एक माह तक मनाया गया। यह अभियान 'मेरी शिक्षा मेरा अधिकार' जैसे बड़े विषय के तहत समावेशी शिक्षा पर केन्द्रित था। अभियान के दौरान समावेशी शिक्षा पर राज्य, जिला, ब्लाक एवं विद्यालय स्तरीय गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें संगोष्ठी, हस्ताक्षर अभियान, रैली, नुक्कड़ नाटक, जिला स्तरीय बैठकें, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकारी, स्लोगन लेखन एवं वाद–विवाद प्रतियोताओं का आयोजन सहयोगी संगठनों, शिक्षकों, बालिका नेताओं एवं युवा समूहों द्वारा किया गया। अभियान के दौरान ही समावेशी शिक्षा की सिफारिशों का एक मांगपत्र विकसित किया गया जोकि ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, केरल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, हरियाणा, और तमिलनाडु में एन ब्लाक, Human Rights Access & Ayushman Trust, लोकमित्र, वर्ल्ड विजन, आक्सफैम, SSSK, उत्ताराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, Assam State Primary Teachers Association, Kerala Pradesh School Teachers Association, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, प्लान, सेव द चिल्ड्रेन, Haryana State Primary Teachers Association, Sustainability Foundation, Tamilnadu Elementary School Teachers Federation, आदि के सहयोग इस अभियान को संचालित किया गया।

ग्लोबल एक्शन वीक फॉर एजूकेशन का समापन समारोह (Culmination Event) –

समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं इसमें मौजूद प्रणालीगत बाधाओं को बदलने की वकालत करने, अधिक समावेशी नीतियों और इससे संबंधित बेहतर नीतियों के कियान्वयन के उद्देश्य से समुदाय, बच्चों, नागर समाज संगठनों, शिक्षकों और शिक्षाविदों के समर्थन के साथ नीतिनिर्माताओं और अन्य हितधारकों से इस विषय पर वकालत करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2019 से 31 मई 2019 तक ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजूकेशन, यूनेस्को, सेव द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड विजन और जोश टॉक्स के सहयोग से भारत के 25 राज्यों में ग्लोबल एक्शन वीक का आयोजन किया गया था।

इस अभियान का समापन 31 मई 2019 को यूनेस्को इंडिया के दिल्ली कार्यालय में किया गया। समापन समारोह में उन सभी 25 राज्यों से आए हुए सहयोगी संगठनों ने अभियान से जुड़े अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में शिक्षक संगठनों, नागर समाज संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षाविदों, विद्यार्थी यूनियन, जनप्रतिनिधियों सहित 91 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सहयोगी संगठनों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यक्रामें के दौरान समावेशी शिक्षा पर आई सिफारिशों और सुझावों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग पत्र तैयार किया गया जोकि प्रधानमंत्री कार्यालय को डाक के द्वारा सौंपा गया। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह, यूनेस्को के शिक्षा विशेषज्ञ श्री मामे ओमर, कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद श्री डी राजा, एजूकेशन इन्टरनेशनल के एशिया प्रमुख श्री आनन्द सिंह, मलाला फन्ड की सुश्री सुनीता जी, सेव द चिल्ड्रेन की सुश्री अलका सिंह एवं सुश्री कमल गौर, अर्थ आस्था से सुश्री राधिका अलकाजी, दलित मुद्दों पर कार्यरत् CSEI संस्था की सुश्री एनी नामला, द वाई पी फाउन्डेशन के श्री मानक, दोस्ताना हमसफर की सुश्री रेशमा प्रसाद, निरन्तर से सुश्री कल्यानी एवं सुश्री अनीता, शिक्षाविद् प्रो० नलिनी जुनेजा एवं CBGA की सुश्री प्रोतिवा कुन्डू ने इस कार्यक्रम में अपने–अपने विचार रखे।

नई शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला–

जून 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन द्वारा उक्त ड्राफ्ट पर विभिन्न हितधारकों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने और इस विषय पर उन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से 10 राज्यों में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गईं।यह परामर्श कार्यशालाएं उड़ीसा, दिल्ली, आंध्र पेदश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, झारखण्ड और असम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, सेव द चिल्डेन, National Law University, Karnataka State Commission For Protection Of Child Rights (Kscpcr), Tata Institute of Social Sciences, Plan India, Oxfam, NERSWN, SEEDS, Shishu Sarothi, Jai Narayan PG College लखनऊ के साथ मिलकर 17 जून से 23 जुलाई के बीच आयोजित किए गए। शिक्षक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रारूप पर विस्तार से चर्चा कर उनकी समझ विकसित करने के प्रयास के साथ ही साथ उनसे सुझाव भी लिए गए जिसे 31 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्र स्तरीय परामर्श कार्यशाला–

राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशालाओं के अतिरिक्त नई शिक्षा नीति पर राष्ट्र स्तर पर भी एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में किया गया। यह कार्यशाला 25 जून 2019 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। कार्यक्रम की चर्चा में मुख्य वक्ताओं के रूप में प्रो0 वृन्दा दत्ता निदेशक ब्म्ब्क् अम्बेडकर विश्वविद्यालय, प्रो0 अनीता रामपाल शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, डा0 प्रदीप चौधरी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, प्रो0 नन्दिता नारायन पूर्व अध्यक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन, प्रो0 अनीता दीघे, डा0 वी मोहन कुमार Indian Adult Education Association एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री कमलाकान्त त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के विषयों सहित शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा की गई। चर्चा से निकले सभी बिन्दुओं को एक दस्तावेज में जोड़ा गया जिसे एनसीई द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एंव विभिन्न सांसदों समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर शिक्षक संगठनों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशालाएं–

10 राज्यों में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की एक परामर्श कार्यशाला के दौरान आई सिफारिशों और सुझावों के बाद एनसीई द्वारा यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर मुख्य रूप से शिक्षक संगठनों के साथ शिक्षकों के नजरिए से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी कम में राज्य स्तरीय शिक्षक संगठनों के सहयोग से राजस्थान के जयपुर, उड़ीसा के भुवनेशवर और उत्तराखण्ड के देहरादून में एक दिवसीय परामर्श कार्यशालाओं का अयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य शिक्षक संघ के जिला एवं ब्लाक स्तरीय पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों कार्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि सभी प्रतिभागी इस प्रारूप को बेहतर तरीके से समझ सके और उस पर प्रभावी ढंग से चर्चा कर सके। इस प्रारूप का विश्लेषण विशेष रूप से शिक्षकों के दृष्टिकोण से किया गया।

दिनांक	राज्य	सहयोग	प्रतिभागी
28 जुलाई, 19	राजस्थान	राजस्थान राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ	35
11 अगस्त, 19	उड़ीसा	ऑल उत्कल टीचर्स फेडरेशन	37
21 अक्टूबर 19	उत्तरांखंड	उत्तरांखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ	48

बालिका नेताओं हेतु नेतृत्व और जनपैरवी निर्माण पर दो दिवसीय कार्यशाला अवधि – 25 जुलाई 2019 से 10 अगस्त 2019

युवा बालिका नेताओं के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान निरन्तर बातचीत के कम में पटना, मेरठ एवं भुवनेश्वर में नेतृत्व और जनपैवरी मुद्दे पर दो दविसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशालाएं गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, एन ब्लाक और PECUC की मदद से आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य उभरती बालिका नेताओं को जनपैरवी के महत्वपूर्ण साधन या उपकरण उपलब्ध कराना था जो उन्हें अपने समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद कर सकें। 80 से भी ज्यादा किशोर बालिकाओं द्वारा इन कार्यशालाओं में सकिय भागीदारी की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर बालिका नेताओं द्वारा इस कार्यशाला के दौरान जनपैरवी पर जो क्षमता हासिल की है उसे वो समुदाय के बीच फलीभूत कर सकें इसके लिए इन युवा नेताओं को एनसीई इंडिया की ओर से एक छोटी सी निधि प्रदान की गई जिससे वे सीखे गए अनुभवों को समुदाय के बीच व्यवहारिक रूप दे सकें।

कम	जिला	राज्य	प्रशिक्षण तिथि	सहयोगी संस्था
1	मेरठ	उ0 प्र0	25एंव 26 जुलाई	एन ब्लाक
2	पटना एवं बक्सर	बिहार	5 एवं 6 अगस्त	गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच अदितिए प्लान इंडिया मदद
3	भुवनेश्वर	उड़ीसा	9 एवं 10 अगस्त	PECUC

नेतृत्व और जनपैरवी पर अभियान अवधि –16 सितम्बर से 12 दिसम्बर

बालिका नेताओं द्वारा बिहार के बक्सर एवं पटना, उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में जोर–शोर से सूचनात्मक अभियान चलाए गए। यह अभियान समुदाय से लेकर जिले एवं राज्य स्तर तक आयोजित किए गए। इन अभियानों में बाल विवाह, बाल श्रम उन्मूलन और बालिका शिक्षा के महत्व सहित विभिन्न मुद्दों को हस्ताक्षर, नुक्कड़ नाटकों और मार्च जैसे बेहद रचनात्मक तरीको का

प्रयोग किया गया । इन अभियानों ने न केवल समुदाय में जागरूकता बढ़ाने में मदद की बल्कि बालिका नेताओं को भी सशक्त करने का काम किया। यह अभियान जहां–जहां किए गए उनका विवरण नीचे संलग्न है –

कम	जिला	राज्य	प्रशिक्षण तिथि	सहयोगी संस्था
1	मेरठ	उ0 प्र0	16 से 30 सितम्बर, 19	एन ब्लाक
2	पटना एवं बक्सर	बिहार	15 अक्टूबर, 19	गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच अदितिए प्लान इंडिया मदद
3	भुवनेश्वर	उड़ीसा	11 से 12 अक्टूबर,19	PECUC

शिक्षा पर पांचवीं एशिया पेसिफिक बैठक

एनसीई, भारत की ओर से सुश्री नूपुर द्वारा 1 से 4 अक्टूबर तक थाईलैंण्ड के बैंकाक शहर में आयोजित शिक्षा पर पांचवीं एशिया पेसिफिक बैठक में हिस्सेदारी की गई। बैठक का विषय आजीवन सीखने और सतत विकास के युग में समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना था।

शिक्षा का अधिकार और आबिदजान सिद्वांतों पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला

एनसीई के प्रतिनिधियों द्वारा आबिदजान सिद्वान्तों पर दो दिवसीय कार्यशाला जोकि 4 एवं 5 अक्टूबर 2019 को थाईलैण्ड के बैंकाक शहर में आयोजित की गई थी, में भागीदारी की गई। कार्यशाला में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मंगोलिया सहित दक्षिण एशिया के गठबंधन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आजीवन अधिगम और शिक्षा की पैरवी पर क्षमतावृद्वि कार्यशाला

आजीवन अधिगम और शिक्षा की वकालत के लिए क्षमतानिर्माण कार्यशाला में एनसीई द्वारा भागीदारी की गई। उक्त कार्यशाला ।ैच्ठ।म् द्वारा 4 से 6 सितम्बर 2019 को थाईलैंड के बैंकाक शहर में जर्मन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन के अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग संस्थान के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से की गई। कार्यशाला में नागर समाज शिक्षा संगठन और वयस्क शिक्षा प्रदाताओं के ज्ञान और कौशल को मजबूत करने में मदद की गई ताकि वे अपने देशों और अन्तर्राष्ट्रीय नीतिगत मंचों पर आजीवन अधिगम और शिक्षा की वकालत कर सकें। उक्त कार्यशाला ने आजीवन अधिगम और शिक्षा की अवधारणाओं को साझा करने और इस विषय पर महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय नीति संबंधी बहस को बढ़ावा देने और आदान–प्रदान करने के लिए एक स्थान प्रदान किया। कार्यशाला में उपस्थित अलग–अलग देशों ने आजीवन अधिगम और शिक्षा में उनकी सरकारों द्वारा निवेश हेतु रणनीति तैयार की गई।

एशिया प्रशांत गठबंधन की बैठक–

20 से 23 अगसत 2019 का वियतनाम के दा नांग शहर में ASPBAE के सभी National Coalitions के राष्ट्रीय समन्वयकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बुनियादी गुणवत्ता का अधिकार, युवा और प्रौढ़ शिक्षा, आपात स्थितियों और संकटों में शिक्षा की चुनौतियों का जवाब देने के लिए विशेष रूप से ध्यान देने, जेंडर को मुख्य धारा में लाने, और शिक्षा के माध्यम से और वकालत योजनाओं और संयुक्त रूप से रणनीतियों पर नवीनतम समझ विकसति करने और एशिया पेसिफिक के पैरवीकारों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समन्वित कार्रवाई हेतु ग्लोबल कैंपेन फॉर एजूकेशन के द्वारा मंच प्रदान करना था।

जेंडर और न्यायसंगत दृष्टिकोण से वित्तीय शिक्षा हेतु वकालत पर योजना बैठक –

एशिया पेसिफिक और भारत में वित्तीय शिक्षा पर चर्चा तथा विचार विमर्श करने के लिए इंडिया इस्लामिक सेंटर में 21 सितम्बर, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई। इस विषय पर समकालीन और उभरते मुद्दों पर गहन समझ हासिल करने के साथ–साथ पैरवी के लिए हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी था। जो एनसीई इंडिया अपने अन्य नेटवर्क के संगठनों के सहयोग से करेगा। ASPBAE फिलीपींस के पैरवी विभाग के श्री रेने राया, NIPFP की डा0 सुकेन्या बोस और श्री सताधुरू सिकदर ने इस विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां दीं जिसके बाद बालिका शिक्षा के लिए बजट में सुधार लाने की वकालत की रणनीतियों के बारे में चर्चा हुई।

अनुसंधान एवं शोध विश्लेशण के लिए SPSS की विधियों पर दो दिवसीय कार्यशाला

शोध एवं अनुसंधान के आंकड़ों का विश्लेशण करने के लिए SPSS जोकि एक डेटा विश्लेषण साफ्टवेयर है, का प्रयोग प्रमुख रूप से मात्रात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। एनसीई इंडिया द्वारा अपने सहयोगी संगठनों के लिए SPSS की विधियों एवं इसको प्रयोग करने के तरीकों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मुख्य उद्देश्य सहयोगी संगठनों इसॅै विधि पर समझ विकसित करना था।

डोर टू डोर अभियान

13 जुलाई, 16 जुलाई और 23 जुलाई, 2019

एनसीई इंडिया द्वारा लोकसभा एवं राज्य सभा सांसदों के साथ डोर टू डोर अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान उनके निवास पर जाकर नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर आयोजित परामर्शों से आए निष्कर्षों और सिफारियों को साझा किया गया। इसके अलावा भारत में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति पर आई स्पॉट लाइट रिपोर्ट एवं भारत में बच्चों के शिक्षा बजट पर विश्लेषित रिपोर्ट एवं सिफारिशों को भी साझा किया गया। 13 जुलाई 2019 से 23 जुलाई 2019 तक चले इस अभियान के दौरान कुल 40 सांसदों का दौरा कर उनसे मुलाकात की गई जिसमें संसद के दोनों सदनों की सभी पार्टियों के सांसद शामिल थे।

30 नवम्बर 2019 से 5 नवम्बर 2019

सांसदों के साथ एक और डोर टू डोर अभियान 30 नवम्बर 2019 से 5 नवम्बर 2019 तक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य 4 की कार्यान्वयन स्थिति पर संसद में चर्चा करना था। इस अभियान के दौरान सांसदों के साथ मुलाकात कर सतत विकास लक्ष्य 4 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चिंता जताई गई। इस अभियान के दौरान लगभग 60 सांसदों से मुलाकात की गई जिन्होंने इस विषय पर ससंद में सवाल हेतु सहमति प्रदान की।

सांसदों एवं राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ सतत विकास लक्ष्य पर बैठक

सांसदों के साथ डोर टू डोर अभियान के कम में 5 दिसंम्बर 2019 को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में लोक सभा एवं राज्य सभा सांसदों के एवं राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 14 सांसदों ने भागीदारी की और शिक्षा के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। बैठक में 'भारत में सतत विकास लक्ष्य 4 की स्थिति' पर चर्चा की गई। चर्चा मुख्य रूप से हाशिए पर खड़े वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव, विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता, विश्वविद्यालयों में बढ़ता शुल्क, शिक्षा के संदर्भ में लड़कियों की सुरक्षा आदि को लेकर हुई। सांसदों ने सतत विकास लक्ष्य 4 का कार्यन्वयन न होने के मुद्दे को ससंद में उठाने की बात कही सांथ ही उन्होंने सभी नागर समाज संगठनों से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में आंकड़े और जानकारी सभी सांसदों को समय–समय पर प्रदान करते रहे।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 'गांधी कथा' का आयोजन

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एनसीई, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं गांधियन फोरम फॉर एथिकल कारपोरेट गवर्नेंस के सहयोग से 27 जुलाई 2019 को AIPTF के कांफेंस हाल में गांधी कथा का अयोजन किया गया। डा0 शोभना राधकृष्णन और डा0 रवि चोपड़ा तथा श्री रमेश कुमार जी सम्मानित सूत्रधार थे। कार्यशाला में गांधीवादी दर्शन और विचारों पर चर्चा हुई। कार्यकम में 35 प्रतिभागियों द्वारा भागीदारी की गई।

राह की रेत में मुझे एड़ियां रगड़ने दो, मुझे मालूम है कि पानी वहीं से निकलेगा

चारों ओर हरियाली, चार दीवारी पर बच्चों के सीखने–सिखाने की गतिविधियों संबंधी सुन्दर से चित्र, किचेन गार्डेन और साफ–सुथरा प्रांगण।जीं हां ये झलक है प्राथमिक विद्यालय दांन्दू पुरकी।संरकारी विद्यालयों को लेकर बनाई गई लोगों की नकारात्मक राय को पूरी तरह नकारता यह प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेष के बनारस जिले के हर हुआ विकास खण्ड में स्थित है। बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है यहां। चाहे आवश्यक कक्षाएं हों, या बच्चों के बैठने की व्यवस्था, सोलरपम्प हो या शुद्वपानी हेत प्यूरीफायर, हाथ धोने के लिए उचित मात्रा में लगे वाशबेसिन, बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की रूचि पूर्ण सामग्री हो या फिर पुस्तकालय इस स्कूल में सब मौजूद है। पढ़ाई के साथ–साथ बच्चों का शारीरिक विकास विकास भी होता रहे इसके लिए बच्चों के खेलने हेतु झूला, बैडमिटन कोर्ट और अन्य खेल सामग्री भीमु है या कराई गई है। और ये सब संभव हो पाया है यहां के प्रधानाचार्य श्री शैलेन्द्र विकम सिंह जी के अथक प्रयास,दूरदर्शिता तथा सामाजिक सहयोग से। श्री शैलेन्द्र विकम सिंह जी जब इस विद्यालय में आए थे तो यहां पर टूटी चार दीवारी, खराब कक्षाएं, खुले और गंदे शौचालय, उखड़ी खिड़कियां,टूटी फर्श सौगात में मिला था।उन्हों ने सबसे पहले विद्यालय के विकास के लिए एक संरक्षक मंडल बनाया जिसमें गांव के प्रबुद्व लोगों के साथ–साथ ग्रामप्रधान भी थे। इस स्कूल को बेहतर बनाने की प्रकिया में विद्यालय प्रबंधन समिति का भी पूरा सहयोग लिया गया। प्रारम्भ में तो लोगों द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया परन्तु धीरे–धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और आज इस विद्यालय को जनपद के बेहतर विद्यालयों में गिना जाता है। बहुत सारे पुरस्कारों से इस विद्यालय को पुरस्कत किया जा चुका है। संरक्षक मंडल के साथ मिल कर प्रधानाध्यापक श्री शैलेन्द्र विकम सिंह जी इस विद्यालय के शैक्षिक स्तर को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्व है।

NATIONAL COALITION FOR EDUCATION

'Shikshak Bhawan', 41-Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: + 91 11 28526851 | **Website:** www.nceindia.org | **Email:** info@nceindia.org

Facebook: facebook.com/nceindia | **Twitter:** twitter.com/nceindia | **Blog:** ncedelhi.blogspot.com

Printed By : KINJAL DESIGNS # 9871227287